

प्रसार भारती  
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)  
प्रादेशिक समाचार एकांश  
आकाशवाणी, पटना

प्रसारण:— अपराह्न 03:10 बजे से।

अवधि:— 05 मिनट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024–25 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एम एस एम ई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। अपने बजट भाषण में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार सम्बद्ध प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। इस पर 32 हजार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। बजट में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष कम्पनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा।

बजट में किसान, महिला, युवा, उद्यमी समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती पचास हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दी गयी है। आम बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख छियासठ हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गयी है। सरकार, जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। महिला नीत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवाज योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024–25 से समाज के हर वर्ग को मदद मिलेगी और उनका सशक्तिकरण होगा। उन्होंने जोर दिया कि इस बजट से गांव, कमजोर वर्ग और किसान समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से युवाओं को अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्ष में पच्चीस करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

वित्त मंत्री ने बिहार के चहमुखी विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। बजट में अमृतसर, कोलकाता, औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी है। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सड़क संरचना के विकास पर छब्बीस हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोध गया, वैशाली तथा दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने के लिए भी सहायता दी जाएगी।

---

वित्त मंत्री की घोषणाओं का राज्य के सियासी, सामाजिक और औद्योगिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बजट का स्वागत करते हुये कहा कि इससे राज्य में विकास को गति और तेज होगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम बजट में बिहार के विकास की पटकथा लिखी गयी है। वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित पैकेज का स्वागत करते हुये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया है। वहीं, विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजन बताया है। राजद की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार को विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े जोर-शोर से बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग करते रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग हो जाना चाहिए।

---

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। एक छोटे अंतराल के बाद आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।